Anant Raj Limited

CIN: L45400HR1985PLC021622
Head Off : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001
Tel : 011-43034400, 23324127, 23323880 **Fax** : 011-43582879
Email : info@anantrajlimited.com **Website :** www.anantrajlimited.com
Regd. Office : CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051
Telefax : (0124) 4265817

ARL/CS/13279 **June 29, 2023**

The Secretary, **The National Stock Exchange of India Limited,** "Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 **Scrip code: ANANTRAJ**	The Manager Listing Department **The BSE Limited**, Phiroze Jee Jee Bhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 **Scrip code: 515055**

Sub: Submission of Newspaper Advertisement -Addendum to the Notice of 38th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on June 29, 2023 in Hindustan Times (English) and Hindustan (Hindi) regarding the Addendum to the Notice of 38th Annual General Meeting of the shareholders of Anant Raj Limited to be held on July 5, 2023.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

For **Anant Raj Limited**

MANOJ KUMAR PAHWA
Digitally signed by MANOJ KUMAR PAHWA
Date: 2023.06.29 16:46:24 +05'30'

Manoj Pahwa
Company Secretary
A7812

Encl: As above

Dr. Juneja's डा.ऑर्थो Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment
घुटनें दर्द, कंधे दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द एवं कलाई दर्द में सहायक आयुर्वेदिक औषधि
8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।
मिलते-जुलते नामों, विज्ञापन से सावधान

अब दर्द भी घुटने टेकेगा...
24x7 Helpline: 7876977777 • www.drorthooil.com

समान नागरिक संहिता पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया

यूसीसी को सांप्रदायिक रंग दे रहा विपक्ष : राजनाथ

आरोप

जोधपुर, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति करता है। जबकि, भाजपा समाज और देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की नीति पर अमल कर रही है।

रक्षा मंत्री ने बुधवार को राजस्थान के शेरगढ़ में कहा कि केंद्र समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ना चाहता है। मगर, विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में एक समान कानून का जिक्र संविधान में भी किया गया है और इसे अमल में लाने के प्रयास हो रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि यूसीसी का एक पहलू महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा है और केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। यूसीसी कोई नया मसला नहीं है, भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में भी इसे शामिल किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था की तरह होते हैं। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी से हों, पद का सम्मान किया जाना चाहिए।

कश्मीरी पंडितों का संगठन भी समर्थन में : उधर कश्मीरी पंडितों के संगठन 'पनुन कश्मीर' ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। संगठन ने कहा इस कानून के लागू होने पर घाटी में कश्मीरी पंडितों की स्थायी वापसी में भी मदद मिलेगी।

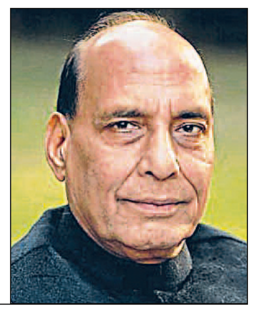

"देश में एक समान कानून का जिक्र संविधान में भी किया गया है और इसे अमल में लाने के प्रयास हो रहे हैं। यूसीसी का एक पहलू महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा है और केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

मोदी के भाषण का बरेलवी उलेमा ने किया समर्थन

तीन तलाक, पसमांदा मुसलमान, एक कानून और यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के भाषण पर बरेलवी उलेमा ने समर्थन किया है। उलेमा ने कहा, एक साथ तीन तलाक देना गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि एक साथ तीन तलाक देने पर पैगम्बर ए इस्लाम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है।

मुद्दा सत्तारुढ़ दल का 'राजनीतिक स्टंट': जदयू

जनता दल (यू) ने केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से समान नागरिक संहिता पर जोर देने को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अनुच्छेद-44 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा, लेकिन यह खंड राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा है, मौलिक अधिकार नहीं है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पक्ष रखेगा

लखनऊ, वि. सं.। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर विधि आयोग के समक्ष जल्द ही अपना पक्ष पेश करेगा। इस बाबत मंगलवार देर रात बोर्ड की कार्यकारिणी की आनलाइन बैठक हुई। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतिवेदन के मसविदे पर चर्चा हुई। बोर्ड प्रवक्ता ने कहा कि यूसीसी देश के सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि कई अन्य समुदायों के पर्सनल लॉ और धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों का हनन करेगी। इसलिए इस संहिता का विचार देशहित में कतई नहीं है। बैठक में कहा गया, देश को समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है और यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों की जनजातियों के हितों का भी सवाल है।

चुनावी तैयारियों पर भाजपा ने किया मंथन

बैठक

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में बदलाव की लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच बुधवार को पीएम आवास पर अहम बैठक हुई। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए।

बैठक को लेकर कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसमें सरकार एवं संगठन में फेरबदल, समान नागरिक संहिता व मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, जुलाई के पहले सप्ताह में कैबिनेट में फेरबदल होने के आसार हैं।

पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला था हमला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा से लौटने के एक दिन बाद मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता की जोरदार पैरवी की थी। साथ ही एकजुट होने की कोशिश कर रहे विपक्ष पर हमला बोला था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पार्टी पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गई है।

गौरतलब है कि दें कि पिछले चार साल में अभी तक सरकार में सिर्फ एक बार फेरबदल हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार में अहम पदों पर बैठे कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा।

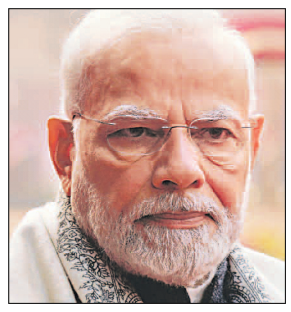

1.21 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन (प्रगति) के 42वें संस्करण की बैठक की। इस दौरान उन्होंने ई-पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 1.21 लाख करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, प्रधानमंत्री की ओर से कुल 12 परियोजनाओं की समीक्षा गई है। इसमें सात परियोजनाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से, दो परियोजनाएं रेल मंत्रालय से परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एक परियोजना इस्पात मंत्रालय और एक परियोजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी थीं।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर मुकदमा

- कांग्रेस की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज किया मामला
- पार्टी और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि मालवीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर वैमनस्य को बढ़ावा दिया और लोगों को उकसाने का काम किया।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि मालवीय द्वारा किए गए एक ट्वीट और उसके साथ साझा किए गए एनीमेटेड वीडियो के सिलसिले में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के सदस्य रमेश बाबू ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि मालवीय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद मालवीय ने उसी ट्वीट को एक कैप्शन के साथ फिर से पोस्ट कर दिया।

कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप : शिकायत दर्ज कराने के लिए 19 जून को बाबू के साथ गए कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि जब भी भाजपा को कानून का डंडा झेलना पड़ता है तो वह हायतौबा मचाती है। उन्होंने कहा, उन्हें (भाजपा को) देश के कानून का पालन करने से समस्या है और उन्हें संविधान से समस्या है।

अमेरिका में देश विरोधियों के साथ दिखे राहुल: स्मृति

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा ने पार्टी के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर बुधवार को कांग्रेस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपनी पार्टी के आरोपों को दोहराया कि उन्होंने अपने अमेरिका दौरे पर देश का विरोध करने वालों के साथ मुलाकात की थी।

ईरानी ने दावा किया कि राहुल ने जिन लोगों से मुलाकात की थी, उनमें अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के करीबी लोग शामिल थे, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम की मेजबानी में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तंजीम अंसारी की भागीदारी के लिए भी राहुल पर हमला बोला। ईरानी ने कहा, जब हर भारतीय को पता है कि जॉर्ज सोरोस क्या करना चाहते हैं तो राहुल उन लोगों के साथ मेलजोल क्यों बढ़ा रहे हैं।

सच को दबाया जा रहा

कांग्रेस शासित कर्नाटक में अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर सबूत दिया कि अगर उसे सत्ता मिलती है तो वह सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकता है।

रेलवे में 2.74 लाख पद खाली: आरटीआई

नई दिल्ली। रेलवे में जून 2023 तक लगभग 2.74 लाख पद खाली हैं, जिनमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में हैं। मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में रेलवे ने कहा है कि लेवल-1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद खाली हैं।

'राहुल, सुप्रिया पर दर्ज केस निरस्त नहीं होगा'

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ दायर प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया है। इनपर फिल्म 'केजीएफ चैप्टर-2' के संगीत के कथित कॉपीराइट उल्लंघन के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।

जुलाई के तीसरे हफ्ते में मानसून सत्र संभव

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। शुरुआत में बैठक पुराने संसद भवन में हो सकती है और बाद में नए भवन में चल सकता है। मानसून सत्र में 20 बैठक हो सकती हैं और यह स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त हो सकता है।

कॉलेजियम में दो नए जज शामिल किए

नई दिल्ली। ग्रीष्मावकाश के दौरान दो वरिष्ठ न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम में बदलाव आया है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई व न्यायमूर्ति सूर्यकांत को कॉलेजियम में शामिल किया गया है।

कोटा में एक और छात्र ने जान दी

कोटा। पुलिस ने बुधवार को कहा कि 17 वर्षीय एनईईटी अभ्यर्थी का शव राजस्थान के इस शहर में उसके छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया। चौबीस घंटे के अंदर यहां किसी कोचिंग छात्र द्वारा की गई यह दूसरी आत्महत्या है।

विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर देवेश भारद्वाज ने कहा कि किशोर की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के निवासी आदित्य सेठ के रूप में हुई है।

'सरकार गरीब, मध्यम वर्ग को भूली'

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गरीब और मध्यम वर्ग को भूल गई है और पूंजीपतियों की संपदा बढ़ाने में व्यस्त है।

राहुल ने कहा, भाजपा को जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाने दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, टमाटर 140 रुपये/किलो, फूल गोभी 80 रुपये/किलो, तुअर दाल 148 रुपये/किलो, ब्रांडेड अरहर दाल 219 रुपये/किलो और खाना पकाने का गैस सिलेंडर 1,100 रुपये के पार। राहुल ने कहा, पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने और जनता से कर वसूली में व्यस्त भाजपा सरकार, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को भूल ही गई।

कांग्रेस नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत

नई दिल्ली, वि. सं.। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर चुनाव में एकजुटता को मजबूत करने की कोशिश की है। बुधवार को हुई बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से प्रदेश के सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी गई। टीएस सिंहदेव ढाई-ढाई साल के फार्मूले को लागू न करने पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं।

सोसाइटी फ्लैट में बकरा लाने पर बवाल, प्राथमिकी दर्ज

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक आवासीय सोसाइटी के कुछ लोगों ने बकरीद से पहले एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में बकरा लाए जाने पर आपत्ति जताई। यह मामला मीरा रोड पर जेपी नॉर्थ की विनय नगर सोसाइटी का है। मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें कुछ लोग चिल्लाते हुए और उस व्यक्ति को बकरा अपने घर ले जाने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह व्यक्ति हर साल पुलिस को बकरीद से पहले अपने घर में बकरा लाने की जानकारी देता है क्योंकि उसके पास बकरा रखने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। अगले दिन बकरा अन्यत्र ले जाता है, वह अपने घर में उसकी कुर्बानी नहीं देता।

खालिस्तान गतिविधियों की आलोचना

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में बढ़ रहे खालिस्तान आंदोलन को लेकर जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना की। उन्होंने कनाडा की सरकार पर वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। बुधवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि कनाडा खालिस्तानी मुद्दे से कैसे निपटता है, यह लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। कनाडा सरकार की प्रतिक्रियाएं वोट बैंक की मजबूरियों के कारण बाधित हुई हैं। यदि कनाडा में ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर आघात करती हैं, तो हमें जवाब देना होगा।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन एच एस आर सी एल), जो मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना को लागू कर रहा है, निम्नलिखित पद के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है।

(i) निदेशक (कार्य)

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया www.indianrailways.gov.in/railwayboard>For IR Personnel>Vacancy Circular>Vacancy Circular_2023 देखें।

आवेदन, संलग्नक के साथ यहां भेजा जा सकता है:
श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव/प्रतिनियुक्ति, रेल मंत्रालय, कमरा नं. 107, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.07.2023 को 17.30 बजे है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

आदिपुरुष फिल्म विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आदिपुरुष फिल्म विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग की गई है।

अदालत में याचिकाकर्ता ममता रानी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्ड, सीबीएफसी द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाणपत्र रद्द करने की प्रार्थना की है। याचिका में फिल्म के डिस्क्लेमर पर गंभीर आपत्ति जताई है और दावा किया है कि इसमें भ्रामक रूप से पेश किया गया है। हिंदू देवताओं राम और हनुमान की भौतिक विशेषताओं और बातचीत शैली का चित्रण बेहद विकृत है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई, ऐसा चित्रण लोगों को अलग तरह के मूल्यों और नैतिकताओं में विश्वास करने के लिए प्रभावित करेगा। याचिकाकर्ता ने दलील दी, 16 जून को रिलीज हुई फिल्म को प्रमाणन और रिलीज के बाद संशोधित किया गया है। रिलीज के बाद इस तरह का बदलाव पूरी तरह से अवैध है।

सीता का चित्रण अश्लील

याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म में सीता का चित्रण अनुचित और अश्लील है। इसमें भगवान हनुमान के एक संवाद का उदाहरण दिया है जिन्हें फिल्म में बजरंगी के नाम से जाना जाता है। प्रतिद्वंद्वी इंद्रजीत के लिए यह तर्क देते हुए कि इस तरह के बयान कभी भी सभ्य समाज में उपयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि ऐसे वाक्य केवल सड़क पर प्रयोग होते हैं।

शिक्षक बहाली पर सरकार के निर्णय से सियासत तेज

बिहार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार सरकार के शिक्षक नियुक्ति में राज्य का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त करने के निर्णय पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस निर्णय का महागठबंधन सरकार के घटक दल भाकपा माले ने भी विरोध किया है। वहीं, भाजपा ने भी सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। रालोजपा और रालोजद ने भी मुखालफत की है।

बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया था कि किसी भी राज्य का निवासी शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकता है। हालांकि, बिहार से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बदलाव किया गया है।

शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न राज्यों के योग्य विद्यार्थी शिक्षक नियुक्ति में भाग ले सकेंगे। इसे पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहारी प्रतिभा का अपमान बताया है। सरकार के इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। वहीं, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा, बीपीएससी से पांच एक वर्ष में 10 हजार से ज्यादा नौकरी देने की क्षमता नहीं है।

अनंत राज लिमिटेड
Anant Raj Limited
सीआईएन: L45400HR1985PLC021622
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051, टेलीफैक्स: (0124) 4265817
प्रधान कार्यालय: एच-65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-43034400, 011-43034426, फैक्स: 011-43582879
ई-मेल: manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट: www.anantrajlimited.com

38वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस का अनुशेष

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 09 जून, 2023 को, अनंत राज लिमिटेड ("कम्पनी") ने एजीएम नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार को सम्पादित करने हेतु, अनंत राज लिमिटेड ("कम्पनी") की 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुलाने के लिए नोटिस जारी किया था जो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बुधवार, 5 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 (भा.मा.स.) पर होनी है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल ने आज यानी बुधवार, 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में, शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री कोसाराजू वीरैया चौधरी (Sh. Kosaraju Veeraiya Chowdary) (डीआईएन: 08485334) की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदित किया और कम्पनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की। ...

एजीएम नोटिस का यह अनुशेष एजीएम नोटिस दिनांक 29 मई 2023 का एक अभिन्न भाग होगा। ...

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते अनंत राज लिमिटेड
हस्ता./-
मनोज पाहवा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 जून, 2023

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की समिति)
जलविज्ञान भवन, रूड़की - 247667, उत्तराखंड

संख्या: 5 (XIII)/2023-24 / NIH-Pur-05 दिनांक: 28.06.2023

निविदा आमंत्रण हेतु नोटिस / NOTICE INVITING TENDER

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की को वार्षिक दर अनुबंध के आधार पर संस्थान में होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कार्यशाला / संगोष्ठी आदि में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित व अनुभवी एजेंसियों से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित दस्तावेज संस्थान के क्रय अनुभाग से प्राप्त करें अथवा संस्थान की वेबसाइट www.nihroorkee.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.07.2023 सायं 3.00 बजे तक है। प्राप्त निविदा की टेक्निकल बिड उसी दिन साथ 4.00 बजे खोली जायेगी।

क्रय अधिकारी / PURCHASE OFFICER

अलग टैरिफ से बदलेगा बिजली बिल

■ **सुमंत बनर्जी**

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली की दर तय करने के लिए 'टाइम ऑफ डे' (दिन के समय) यानी टीओडी टैरिफ लागू करने की जानकारी दी थी। यह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अगले साल और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2025 में लागू होगा। यह टैरिफ क्या है, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं...

क्या है टाइम ऑफ डे टैरिफ? : सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 में संशोधन कर मौजूदा बिजली शुल्क प्रणाली में दो बदलाव किए हैं। यह बदलाव टीओडी टैरिफ की शुरुआत और स्मार्ट मीटर से जुड़े प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित है। इस टैरिफ के तहत दिन के अलग-अलग समय के लिए बिजली की अलग-अलग दरें लागू होंगी। इससे दिन में बिजली खपत का प्रबंधन कर बिल में 20 फीसदी तक की कमी की जा सकती है। हालांकि रात में यह उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इससे बिजली कंपनियों को मांग को संतुलित करने में मदद मिलेगी वहीं उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत का प्रबंधन और बिलों को नियंत्रित करने की क्षमता मिल सकेगी।

ऐसे आएगा बदलाव

उन परिवारों में जहां पति-पत्नी दोनों कार्यरत हैं और बिजली का अधिकतर इस्तेमाल रात में होता है, वहां बिल में बढ़ोतरी होगी। वहीं अब घर बिजली के इस्तेमाल से रात के समय में होने वाली बढ़ोतरी की कुछ भरपाई करने में सक्षम हो सकेंगे। आम तौर पर सुबह स्कूल और कार्यालय खुलते ही बिजली की खपत बढ़ जाती है। दोपहर में बच्चों के घर लौटने के वक्त कारखानों और कार्यालयों में काम हो रहा होता है और शाम के वक्त बिजली की खपत होती है। यह तब होता है, जब घरों में एसी-कूलर व सर्दियों में हीटर व गीजर खूब प्रयोग होता है।

mint

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

विज्ञप्ति

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, सुगम बनाने की दृष्टि से एकल अवसरीय पंजीकरण (ओ0टी0आर0) की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्तमान में एकल अवसरीय पंजीकरण (ओ0टी0आर0) प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर यथास्थान लिंक करके वांछित सूचनायें भरकर पूर्ण की जा सकती है। अभ्यर्थीगण एकल अवसरीय पंजीकरण (ओ0टी0आर0) प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा न हो। एक बार ओ0टी0आर0 पंजीकरण हो जाने के बाद उसमें अधिकतम तीन बार पुनः संशोधन किया जा सकता है। ओ0टी0आर0 प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण कर अभ्यर्थियों को ओ0टी0आर0 पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः जिम्मेदार होगा।

वर्तमान में समस्त ऑनलाइन आवेदनों हेतु ओ0टी0आर0 व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू है अब कोई भी अभ्यर्थी किसी विज्ञापन के सापेक्ष बिना ओ0टी0आर0 के आवेदन नहीं कर सकता। अतः अभ्यर्थीगण इस क्रम में वर्तमान विज्ञापनों के साथ-साथ भविष्य में जारी होने वाले विज्ञापनों के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु O.T.R.(One Time Registration) कर लें जिससे अभ्यर्थियों को समस्त विज्ञापनों के सन्दर्भ में प्रक्रियाओं की अनुपालना में सुगमता होगी।

संख्या: 1015/11/ई-1/2022-23
दिनांक: प्रयागराज, 28 जून, 2023

अशोक कुमार
(सचिव)

Branded T.SHIRT SALE
MEN, WOMEN & KIDS
upto 60% off
Introducing huge range of Shorts & Lowers
By Economy Sales: 9212758425
ARROW PARK AVENUE ColorPlus LOUIS PHILIPPE Levi's
• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

Bengal top beneficiary of govt's power borrowing incentives

Rajeev Jayaswal
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: West Bengal emerged the top beneficiary of the centre's ₹66,413 crore-additional borrowing incentives for undertaking power sector reforms in 2021-22 and 2022-23, followed by Rajasthan and Andhra Pradesh, according to an official data.

Based on the recommendations of the Union power ministry, the Centre allowed 12 states to raise additional financial resources of ₹66,413 crore in 2021-22 and 2022-23, Union finance ministry said on Wednesday.

While West Bengal topped the list of 12 states and availed ₹15,263 crore cumulative amount of additional borrowing for 2021-22 and 2022-23, Rajasthan's share in the pie was ₹11,308 crore and Andhra Pradesh's ₹9,574 crore.

"The initiative has spurred state governments to initiate the reform process, and several states have come forward and submitted details of the reforms undertaken and achievements of various parameters to the Ministry of Power," the finance ministry added in a statement.

The initiative was announced by Union finance minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget for FY22. Under this scheme, an additional borrowing space of up to 0.5% of the gross state domestic product (GSDP) is available to the states annually for a four-year period starting from 2021-22. This additional financial window is dependent on implementation of specific reforms in the power sector by states.

THE PLAN GRANTS STATES EXTRA BORROWING SPACE, SUBJECT TO THE IMPLEMENTATION OF REFORMS IN THE POWER SECTOR

"In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 2021-2022. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of GSDP will also be provided subject to conditions," the FM said in her speech on February 1, 2021.

States can continue to avail this special dispensation linked to power sector reforms in the current financial year (2023-24). "An amount of Rs 1,43,332 crore will be available as an incentive to States for undertaking these reforms in 2023-24. States that were unable to complete the reform process in 2021-22 and 2022-23 may also benefit from the additional borrowing earmarked for 2023-24 if they carry out the reforms in the current financial year," the finance ministry said.

Other beneficiaries reforms undertaken in 2021-22 and 2022-23 are -- Kerala (received additional borrowing permission for ₹8,323 crore), Tamil Nadu (₹7,054 crore), Uttar Pradesh (₹6,823 crore), Sikkim (₹361 crore), Odisha (₹2,725 crore), Meghalaya (₹192 crore), Manipur (₹180 crore) Himachal Pradesh (₹251 crore), and Assam (₹4,359 crore).

The objective of granting financial incentives for undertaking power sector reforms is to improve operational and economic efficiency within the sector and promote a sustained increase in paid electricity consumption, the finance ministry said.

To avail this incentive, states must undertake a set of mandatory reforms and meet stipulated performance benchmarks — progressive assumption of responsibility for losses of public sector discoms by the state government, transparency in reporting of financial affairs of power sector, among others.

HC SEEKS BENGAL SEC REPORT ON CAPF DEPLOYMENT AHEAD OF POLLS

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: The Calcutta high court on Wednesday ordered the West Bengal state election commission (SEC) to file a report on how it plans to deploy Central armed police forces (CAPF) across the eastern state before the July 8 panchayat polls, lawyers familiar with the development said.

The SEC informed a bench headed by chief justice TS Sivagnanam that though it had sought 822 companies of CAPF from the Centre, 458 companies were yet to arrive in Bengal.

"Expressing concern over the ongoing violence, the court asked the SEC to file a report by Monday on how it plans to deploy state police and CAPF to ensure peaceful polling," lawyer Lokenath Chatterjee said.

Chatterjee is the head of the Bharatiya Janata Party's state legal cell which filed a public interest litigation (PIL) on June 9, a day after the three-tier panchayat elections were announced. The Congress, too, filed a similar petition on the same day.

The high court posted the matter for further hearing on Monday, the lawyer added.

{ FROM PAGE 1 }

TCS ROLL-OUT

requesting anonymity.

The finance ministry, however, said in the statement that the decision to postpone the May 16 notification was to "give adequate time to banks and card networks to put in place requisite IT-based solutions" in case of higher TCS rates.

"This would mean that transactions through international credit cards while being overseas would not be counted as LRS and hence would not be subject to TCS," it added.

Experts said the government's statement on Wednesday is still ambiguous in intent and it appears that it is merely postponing a problem instead of resolving it conclusively.

The finance ministry said for the first ₹7 lakh remitted outward in a financial year under the LRS there shall be no TCS on all categories of payments through all modes regardless of the purpose.

"Beyond this ₹7 lakh threshold, TCS shall be a) 0.5% (if remittance for education is financed by education loan); b) 5% (in case of remittance for education/medical treatment); c) 20% for others," it said.

"For purchase of overseas tour program package... the TCS shall continue to apply at the rate of 5% for the first ₹7 lakh per individual per annum; the 20% rate will only apply for expenditure above this limit," it said.

Experts criticised the move as multiple tax rates would make the system complicated and lead to a compliance nightmare. They also pointed out that the move is also a roundabout way of reducing the overall LRS limit of $250,000 a year.

At least three experts, who did not wish to be named, said the government's decision to bring in international credit cards under the $250,000 limit goes against the grain of the LRS, and also runs counter to the medium-term objective of convertibility.

HT on May 20 wrote that the government's move effectively reduced the LRS limit.

"If the idea is to reduce the amount Indians can spend or invest overseas in a year, or use to buy assets such as houses or stocks, then it is anti-reformist, and goes against the original reasons why LRS was introduced. If the idea is to crack down on untaxed income finding its way overseas — a cumbersome process given that even credit card spends are on the radar anyway — going after individual violators perhaps makes more sense than a sweeping rule change," it pointed out.

The new Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, notified last month on May 16, deleted a section that exempted credit card payments from the LRS. Thus, foreign remittances made through credit cards would have come under the LRS limit of $250,000 from July 1.

After the Reserve Bank of India on May 16 issued amended rules to include usage of international credit cards under the LRS in line with debit cards, the finance ministry on May 18 issued a clarification exempting business expenditure undertaken through credit cards "subject to verifying the bona fide of the transaction".

On May 19, after more concerns were raised, the finance ministry issued a statement exempting transactions up to ₹7 lakh a year from the TCS requirement.

ANANT RAJ LIMITED
Anant Raj Limited
CIN: L45400HR1985PLC021622
Registered office: Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122051, Telefax: (0124) 4265817
Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001, Tel: 011-43034400, 011-43034426 Fax: 011-43582879
E-mail : manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

We wish to inform you that on 09th June 2023, Anant Raj Limited ("the Company") has issued Notice for convening the 38th Annual General Meeting ("AGM") of Anant Raj Limited ("the Company") to be held on Wednesday, July 5, 2023 at 10:00 A.M. (IST) at the registered office of the Company to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is informed that the Board of Directors at its Board Meeting held today i.e. Wednesday, June 28, 2023, have considered and approved the appointment of Sh. Kosaraju Veerayya Chowdary (DIN: 08485334) as an Additional Director and also, designated him as a Non-Executive Independent Director of the Company, subject to approval of shareholders. However, being an additional Director, he will hold such office upto the date of the ensuing AGM.

The Board of Directors of the Company has also received a candidature u/s 160 from a member of a Company signifying his intention to propose the appointment of Sh. Kosaraju Veerayya Chowdary as an Independent Director of the Company.

Thus, the proposal of regularization of Sh. Kosaraju Veerayya Chowdary as Independent Director is to be included in the Notice of AGM. An Addendum to notice of AGM for additional agenda item no. 5 i.e. "To appoint Sh. Kosaraju Veerayya Chowdary (DIN: 08485334) as an Independent Director" along with Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 including all the requisite details are available on the Company's website at **www.anantrajlimited.com** and websites of the Stock Exchanges i.e **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** for the information of investors/ members etc.

This Addendum to the AGM Notice shall form an integral part of the AGM notice dated 29th May 2023. A separate intimation in this connection shall also be sent to the shareholders.

We wish to reiterate that the entire contents of the AGM Notice, including the date, time, and business to be transacted at the AGM relevant disclosures, etc. shall remain the same.
The AGM Notice should be read in conjunction with the above disclosure/ information.

By order of the Board of Directors
For Anant Raj Limited
Sd/-
Manoj Pahwa
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : June 28, 2023

INSTITUTE OF NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY, MOHALI
(An Autonomous Institute of Department of Science and Technology, GoI)
Knowledge City, Sector 81, SAS Nagar, Mohali-140306, Punjab

No. 24(3)/2022-INST Date: 28.06.2023

ADVERTISEMENT FOR THE POSITION OF RESEARCH ASSOCIATE-I (RA-I)

Institute of Nano Science and Technology (INST) invites applications for engagement of RA-I on contractual basis under project entitled "Development of single catalytic system for photocatalytic hydrogen production and thermal CO_2 conversion". **Last date of receipt of application: 12.07.2023.** For details, candidate may visit **https://inst.ac.in/careers**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Ministry of Railways, Government of India invites applications from eligible persons for the following post in National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) which is implementing Mumbai-Ahmedabad high speed train project:

(i) Director (Works)

For detailed advertisement, kindly refer to **www.indianrailways.gov.in/railwayboard>For IR Personnel>Vacancy Circular>Vacancy Circular_2023**

The applications, along with enclosures, may be sent to:

Shri Manoj Kumar, Joint Secretary/Deputation, Ministry of Railways, Room No. 107, Rail Bhawan, New Delhi-110001.

Last date for receipt of applications is **17.30 hrs. on 28.07.2023**. Applications received after the last date will not be entertained and no correspondence will be entertained in this regard.

SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
RAE BARELI ROAD, LUCKNOW, U.P (INDIA)
EPBX NO. 0522-2494000/ 2495000/ 2668700/ 2668800/ 2668900
Fax: 0522-2668017/ 2668078

Recruitment Notice

Online applications for the post of **"Joint Director (Admin)"** (on deputation) & **"Medical Superintendant"** were invited through Institute website and different News Papers. Vide Advt. no. I/04//Rectt./2023-24 dated 05.05.2023.

The weblink portal for the above said posts will remain active as under.

Application Form Opening Date- **22nd June, 2023**
Application Form Closing Date- **10th July, 2023**
Visit website **www.sgpgims.org.in**

Advt. No. I/14/Rectt/2023-24 **(Joint Director Admn.)**

ICAR-INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE
GWALIOR ROAD, NEAR PAHUJ DAM, JHANSI-284 003

F.No. 1-7/NLM/VKY/Rectt/2023 Dated: 28.06.2023

WALK-IN-INTERVIEW

WALK-IN-INTERVIEW for **One temporary post** of **Research Associate** at consolidated Amount Rs. 49000/- per month for Master's Degree and Rs. 54000/- per month for Doctoral Degree+H.R.A. admissible (HRA will be given only if accommodation is not provided in the Institute campus) Project: **"Development of effective mass propagation technique for rapid multiplication and easy transportation of quality planting material in Bajra Napier hybrid"** will held on dated 11.07.2023 at 11.00 AM at IGFRI, Jhansi. For more details i.e. Qualification, Emoluments & other condition please see the full advertisement at Institute's website **www.igfri.icar.gov.in**.

Asstt. Administrative Officer (Rectt.)

Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI)
(Under Department of Pharmaceuticals, Govt. of India)
E-1, 8th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055
Telephone: 011-49431800/49431811/49431829/49431833/49431854/49431874
Website: janaushadhi.gov.in

e-TENDERING NOTICE FOR SUPPLY OF SURGICAL/ CONSUMABLES AND MEDICAL DEVICES

Online bids for procurement of 171 Surgical / Consumables and Medical Devices for **"Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP)"** are invited by PMBI. Last date and time for submission of e-Tender no. PMBI/SURGICAL/RC-210/2023, published on 20.06.2023 for procurement of 171 items is on 12.07.2023 (Wednesday) up to 17.00 Hours. For detailed eligibility criteria, terms & conditions of the e-tender, please see the websites **https://janaushadhi.gov.in** & **http://eprocure.gov.in/eprocure/app**

Applications invited for Senior Legal Consultants and Legal Consultants

Advertisement No. AA-11034/1/2021-CL&FS-Part(1)-2

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) invites applications from Indian citizens, for their whole-time services as individual consultants, on a contractual basis, for an initial period of three years, extendable by two years, as following:

S. No.	Category of consultants	Number of consultants
1.	Senior Legal Consultant	Two
2.	Legal Consultant	Three

The detailed advertisement along with terms and conditions, last date of receipt of application and eligibility criteria etc. with Application form, is available on **www.meity.gov.in/**

Applicants may email the scanned copy of their duly completed application form, along with their curriculum vitae to **gccyberlaw@meity.gov.in** ***within 21 days of the release of the advertisement in the newspaper.***

CBC 06101/11/0004/2324

MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(An Institution of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)
Bhopal-462003 (M.P.) INDIA

No.AB/Estt./Tem.Fac./2023/1088 Date :28/06/2023

Walk-in-Interview for Appointment of Temporary Faculty

Walk-in-Interview for appointment of Temporary Faculty is to be held in the Departments as given below:

(1) Architecture & Planning **(2) Computer Science & Engineering**
(3) Chemistry **(4) Physics**
(5) Mathematics, Bio-informatics & Computer Applications
(6) Civil Engineering **(7) Humanities**

Candidates who have already served in the Institute for more than five semesters in their entire career, their candidature shall not be considered. Interested candidates may submit application and resume on plain paper along with photocopies of certificates & testimonials in the office of the concerned Head of Department on or before the date & time of Interview. Preference shall be given to the candidates having Ph.D. Degree.
Detailed advertisement for qualification, remuneration, date of interview etc. may be referred on Institute website **www.manit.ac.in**

REGISTRAR

NORTHERN RAILWAY
OPEN E-TENDER NOTICE
Azadi Ka Amrit Mahotsav

Invitation of tender through E-Tendering (E-Procurement Systems)

The Sr. Divisional Engineer-IV, Northern Railway, Delhi Division for and on behalf of President of India invites E-Tender on prescribed form for the following work.

1.	Name of work with its location	1. Construction of Limited Height Subway (LHS) at km. 71/31-72/2 on DLI-BTI section connecting Indira Colony and Shyam Colony at Rohtak .(NIT 28-W-IV-23-24)
2.	Approx. cost of work	(1) Rs. 5,86,12,131.78
3.	Earnest money	(1) Rs. 4,43,100.00
4.	Date and Time of submission of tender and opening of tender	Bidding Start date for work no. Up to 15:00 hrs. on 07.07.2023 opening of e-Tender at 15:00 hrs. on 21.07.2023.
5.	Website particulars, published e-tender notice location etc. complete details of tender can be seen and website where the tender form can be downloaded	Above tender available on IREPS site i.e. www.ireps.gov.in

No. 128-W/260/Tender Notice/28-W-IV/23-24 Date : 28.06.2023 2000/2023

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

PUNJAB STATE WAREHOUSING CORPORATION, CHANDIGARH
SCO 74-75, BANK SQUARE, SECTOR-17B, CHANDIGARH
E-mail: ctopswc@punjab.gov.in

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER NO. : PSWC/CTO/2023-24/06

Punjab State Warehousing Corporation invites online bids for Expansion/Extension of Centrally Monitored Electronic Surveillance System for PSWC Owned Warehouse locations.

Closing date and time: 24.07.2023 at 12.00 noon
For details log on to https://eproc.punjab.gov.in
Note: Any addendum(s)/Corrigendum(s) to the Tender Notice shall be published on the above website only.

25400 **Managing Director**

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया(REAP-2023)
तकनीकी संस्थानों /महाविद्यालयों के पंजीयन एवं प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान राज्य में स्थित राज्य विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्धता प्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के तकनीकी पाठ्यक्रमों में B.Tech./B.E. तथा B.Arch.के सत्र 2023–24 के लिए प्रथम वर्ष में राजस्थान राज्य एवं राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधित आवश्यक सूचनाः–

COURSES →	B.E. / B.Tech.	B.ARCH.
अभ्यर्थियों हेतु	ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन फॉर्म का शुल्क (₹295/-) जमा करने की **संशोधित अंतिम तिथि** :–**05.07.2023**	ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन फॉर्म का शुल्क (₹295/-) जमा करने की **संशोधित अंतिम तिथि** :–**31..07.2023**
	ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन फॉर्म जमा करने की **संशोधित अंतिम तिथि** :– **07.07.2023**	ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन फॉर्म जमा करने की **संशोधित अंतिम तिथि** :– **02.08.2023**
	अस्थायी अभ्यर्थी योग्यता सूची (Tentative Merit List) **reap2023.com** पोर्टल पर जारी किये जाने की तिथि :–**10.07.2023**	अस्थायी अभ्यर्थी योग्यता सूची (Tentative Merit List) reapbarch2023.com पोर्टल पर जारी किये जाने की तिथि :– **04.08.2023**
	संस्थान एवं ब्रांच विकल्प भरे जाने की अवधिः– **दिनांक 10.07.2023 से दिनांक 18.07.2023**	संस्थान एवं ब्रांच विकल्प भरे जाने की अवधिः– **दिनांक 04.08.2023 से दिनांक 13.08.2023**
	Counselling समय सारणी (Schedule) की विस्तृत जानकारी हेतु reap2023.com पोर्टल को विजिट करे	**Counselling समय सारणी (Schedule) की विस्तृत जानकारी हेतु reapbarch2023.com पोर्टल को विजिट करे**
संस्थानों हेतु	ऑनलाईन पंजीयन फॉर्म शुल्क सहित आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि :–**29.06.2023**	ऑनलाईन पंजीयन फॉर्म शुल्क सहित आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि :–**11.07.2023**
	ऑनलाईन पंजीयन फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि :–**07.07.2023**	ऑनलाईन पंजीयन फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि :–**17.07.2023**
	नोटः– • पंजीयन में किसी प्रकार की देरी के लिए संयोजक रीप–2023 उत्तर दायी नहीं होगा। • पंजीयन शुल्क (₹11800/-) केवल निजी अभियांत्रकी महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जमा कराया जाना है। किसी भी संस्थान(राजकीय/निजी संस्थान) द्वारा नियत तिथि के पश्चात् पंजीयन करवाने पर पंजियन शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क (₹15000/- + 18% GST) भी लिया जावेगा। • संस्थानों/महाविद्यालयों को पंजीयन के पश्चात् संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित पंजीयन फॉर्म, पंजीयन शुल्क जमा कराने की रसीद, निर्धारित शपथ पत्र आदि REAP–2023 कार्यालय में दिनांक 10.07.2023 सांय 05:00 बजे (For B.E. / B.Tech course) तक जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। • संस्थानों/महाविद्यालयों को पंजीयन के पश्चात् संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित पंजीयन फॉर्म, पंजीयन शुल्क जमा कराने की रसीद, निर्धारित शपथ पत्र आदि REAP–2023 कार्यालय में दिनांक 20.07.2023 सांय 05:00 बजे (For B.Arch Courses) तक जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।	

ऑनलाईन आवेदन मय पंजीयन, विस्तृत विवरण एवं नवीनतम जानकारियों हेतु समय–समय पर विजिट/सम्पर्क करें:

Websites:-
for B.E. / B.Tech. - www.reap2023.com, for B.ARCH. - www.reapbarch2023.com
For Support -help.reap2023.com
Contact Mobile No. - 9462015808 , 9462015080

CONVENOR, REAP-2023
Address: Centre for Electronic Governance, Jhalana Doongari, Jaipur-302004

Raj.Samwad/C/23/4800

Office of the Superintending Engineer
6th Circle P.W.D. Uttarkashi
E-Mail sepwduki@rediffmail.com

Letter No.: 2620/56 M-06/2023-24 Date: 28.06.2023

National Competitive Bid (E-Tendering)

On behalf of the Hon'ble Governor, Uttarakhand, Superintending Engineer 6th circle, PWD, Uttarkashi invites Tender through e-tendering (Two bid system) for the following work. All the information regarding tender shall be available on web site http://www.uktenders.gov.in from dated 03.07.2023.

Sl. No.	Name of Work	Earnest Money (Rs. in Lacs)	Validity of Tender (in Days)	Cost of Tender Document (In Rs.)	Time of Completion (in Month)	Class of Contractor
1	2	3	4	5	6	7
1	Repair work of Collectorate residential colony of district headquarter Uttarkashi.	7.00	120 Days	5000.00 +18% GST	18 Months	Registration in **'A'** Class or above for Building Works in Central Govt./State Govt. Any Govt. Undertaking.

Ministry of Communications, Department of Posts, Civil Wing

PRESS NOTICE INVITING COMPOSITE PERCENTAGE RATE e-TENDER

Executive Engineer (C), Postal Civil Division, Jaipur, invites on behalf of The President of India, online percentage rate (CPWD-7) Composite e-tenders for the following work:-

Sl. No	Name of Work	NIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Period of Completion	Last date & time submission of bid
1	Construction of Small Post Office Building at Rawatsar under Sriganganagar Division.	28/EEPCD/JP/2023-24	Rs. 4760311/- [Rs. 4411623/- (Civil Portion) & Rs. 348688/- (Electrical Portion)]	Rs. 95206/-	187 (One Hundred and Eighty Seven) days	Upto 1100 Hrs on 12.07.2023
2	Construction of Small Post Office Building at Dudhwakhara under Churu Division.	29/EEPCD/JP/2023-24	Rs. 3926893/- [Rs. 3589753/- (Civil Portion) & Rs. 337140/- (Electrical Portion)]	Rs. 78538/-	187 (One Hundred and Eighty Seven) days	Upto 1100 Hrs on 12.07.2023
3	Construction of Small Post Office Building at Jojawar under Pali Division.	30/EEPCD/JP/2023-24	Rs. 3926522/- [Rs. 3565050/- (Civil Portion) & Rs. 361472/- (Electrical Portion)]	Rs. 78530/	187 (One Hundred and Eighty Seven) days	Upto 1100 Hrs on 14.07.2023
4	Renovation of DO Hall, ASP Hall at 2nd Floor, Roof Treatment, Preparation of Feed Room and Provision of Ladies Toilet for Jodhpur HPO Building Jodhpur Division.	31/EEPCD/JP/2023-24	Rs. 32,94,311/- (Civil Work)	Rs. 65,886/-	120 (One Hundred and Twenty) days	Upto 1100 Hrs on 14.07.2023

The bid form and other details can be obtained from the website **https://dopcivil.euniwizarde.com**.

Executive Engineer
Postal Civil Division, Jaipur

INDIAN INSTITUTE OF CARPET TECHNOLOGY
IICT
Under the aegis of O/o Development commissioner (Handicrafts) Ministry of Textiles, Govt. of India
Affiliated with APJAKTU, Lucknow & approved by AICTE, Govt. of India
BHADOHI - 221401 (UP)

The Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi is offering B. Tech. degree in Carpet and Textile Technology since 2001 with excellent placement record in various national and international firms in the field of carpet and textiles. It is a centrally funded technical institute under Ministry of Textiles, Govt of India, Office of Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi. The institute provides hostel facilities for boys & girls with internet and sports facilities.

Admission (Session 2023-24)
B.Tech. (Carpet and Textile Technology)
(NBA Accredited)

- **1st Year B.Tech. (All India Quota) -30 seats through JoSAA/CSAB counselling (visit https://josaa.nic.in/https://csab.nic.in/)**
  (UP state Quota) - 30 seats through AKTU, Lucknow counselling (visit https://aktu.ac.in/https://cuet.samarth.ac.in/)
- **2nd Year B.Tech. Lateral Entry - 06 seats through AKTU, Lucknow counselling (visit - https://aktu.ac.in/https://cuet.samarth.ac.in/)**

For more information, Contact: 7905752113, 9450254736, 9935792794 (10 am to 5 pm only on working days) or visit website: http://iict.ac.in

CBC 41103/11/0007/2324